

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 08.09.2026 को जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति (DWSM) की बैठक जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहे।

S.No	Name	Designation	Department
1	श्री दिनेश कुमार श्रीवास्तव	मुख्य विकास अधिकारी	विकास विभाग
2	श्री अरुण कुमार उपाध्याय	क्षेत्रीय वनाधिकारी	वन विभाग
3	डा० पंकज राय	मुख्य चिकित्साधिकारी	चिकित्सा
4	श्री सुनाब चन्द सरोज	जिला विकास अधिकारी	विकास
5	श्री संजय मैत्रे	अधिरासी अभियन्ता	सिंचाई
6	श्री अरुण बाबू गुप्ता	अधिरासी अभियन्ता	मलकूर
7	श्री सुनाब चन्द सरोज	परियोजना निदेशक	डी०आर०डी०ए०
8	श्री सतीश उपाध्याय	बेसिक शिक्षा अधिकारी	शिक्षा
9	श्री सोनप्रकाश गुप्ता	जिला कृषि अधिकारी	कृषि
10	श्री धनपाल सिंह	जिला सूचना अधिकारी	सूचना
11	श्री रामेश्वर दयाल	अधिरासी अभियन्ता	जल निगम (ग्रामीण)
12	श्री चन्दलाल सिंह	डी०सी०	डी०पी०एन०
13	श्री शर्करा रत्न	सहायक अभियन्ता (थि०/डि०)	जल निगम (ग्रामीण)
14	श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह	डी०पी०एन०	टी०पी०आई संस्था
15	श्री दीपक शर्मा	प्रोजेक्ट मैनेजर	मैसर्स एल०सी० इन्फ्रा
16	श्री अनूप कुमार सिंह	प्रोजेक्ट मैनेजर	मैसर्स एल०सी० इन्फ्रा
17	श्री शिवा/जायल दुबे	प्रोजेक्ट मैनेजर	मैसर्स बंगलएसजार्



बैठक के दौरान JJM District Dashboard पर उपलब्ध विभिन्न बिन्दुओं एवं आकड़ों पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा विस्तृत एवं गहन समीक्षा की गयी जो निम्नवत है।

Table No.1 : Jal Nigam Under Construction (UC) Scheme Progress.

जल निगम की निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति के सम्बन्ध में अधिरासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि जल निगम की 3 परियोजनायें हैं, जिसमें 07 राजस्व ग्राम आच्छादित है। मसीना, प्यारेपुर सलामुद्दीनपुर तथा सरवां (परदहों)।

मसीना पेयजल योजना- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि इस ग्राम पंचायत में दो अनुबन्ध किये गये थे। एक अनुबन्ध पाइप लाइन का था, दूसरा पानी की टंकी व पम्प हाउस के साथ किया गया। पाइप लाइन का कार्य अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण हो गया था एवं 3 साल 6 माह से क्लोरिन युक्त पानी की आपूर्ति डायरेक्ट की जा रही है। दूसरा अनुबन्ध के सापेक्ष पम्प हाउस का कार्य हो गया था, परन्तु पानी की टंकी का कार्य बाटमडोम तक 95 प्रतिशत तक पूर्ण हो पाया था। शेष कार्य न करने के कारण अनुबन्ध निरस्त कर दिया गया। दुबारा अनुबन्ध किया गया है, जिसके अनुसार 19.10.2026 तक शेष कार्य गुणवत्ता से पूर्ण करा लिया जायेगा।

प्यारेपुर सलामुद्दीनपुर पेयजल योजना- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि बोरिंग का कार्य पूर्ण हो गया है। पम्प हाउस का कार्य पूर्ण हो गया है। पाइप लाइन का कार्य 50 प्रतिशत पूर्ण है तथा कनेक्शन 50 प्रतिशत तक पूर्ण है। पानी की टंकी का कार्य चल रहा है। थर्डब्रेस तक कार्य हुआ है। अर्थात् 40 प्रतिशत तक पूर्ण है। सम्पूर्ण परियोजना का कार्य 68 प्रतिशत हुआ है। नवम्बर 2026 तक कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

सरवों (परदहों) पेयजल योजना- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि दो द्यूबवेल की बोरिंग हो गयी है। दो पम्प हाउस बन गया है। विद्युत कनेक्शन हो गया है। पाइप लाइन का कार्य 03 कि०मी० हुआ है। पानी का कनेक्शन नहीं है। पानी की टंकी का निर्माण नहीं हुआ है। कुल मिला कर परियोजना का कार्य मात्र 29 प्रतिशत हुआ है। अवशेष कार्य के लिये टेण्डर की नयी प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी है। सितम्बर 2027 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

उपरोक्त तीनों परियोजनाओं को शीघ्रता एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने के लिये अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया।

Table No-1A: Jal Nigam Operation and Maintenance Scheme Progress.

अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि जल निगम की कुल 53 परियोजना आपरेशन एवं मेन्टेनेन्स में है। इसमें 124 राजस्व ग्राम आच्छादित है। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि 72 राजस्व ग्राम में पूर्ण रूप से कार्य कर रही है, 50 राजस्व ग्राम में आंशिक रूप से कार्य कर रही है, 02 परियोजनायें नान फंक्शनल है। भीरा पेयजल परियोजना में मेन लाइन डालने का कार्य बाधित है। विद्युत विभाग व खातेदार से विवाद होने के कारण कार्यरूका है। विवाद को सुलझा कर शीघ्र कार्य प्रारम्भ कराने के लिये निर्देशित किया गया। फतेहपुर ताल नरजा पेयजल योजना पर बोरिंग फेल है। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि बोरिंग के लिये धनराशि उपलब्ध नहीं है। धनराशि उपलब्ध होते ही कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) को 30 सितम्बर 2026 तक शीघ्रता एवं गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण करने के लिये निर्देशित किया गया।

Table No-1B: Jal Nigam Retrofit Scheme Progress.

अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि जल निगम की 15 परियोजनायें रेट्रोफीटिंग में है। जिसमें 45 राजस्व ग्राम आच्छादित है। सभी परियोजनायें पूर्ण है। 06 परियोजनायें वित्तीय रूप से पूर्ण हो चुकी हैं। भुगतान हो जाने पर 09 परियोजनायें भी वित्तीय रूप से पूर्ण हो जायेंगी। रेट्रोफीटिंग के अन्तर्गत पूर्ण होने वाली परियोजनाओं का सत्यापन खण्ड विकास अधिकारी से कराने के लिये निर्देशित किया गया।

Table No-2: Physical Progress Phase wise.

अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि जनपद मऊ में फेज-2 में मेसर्स एल.सी.इन्फ्रा वर्ष 2021 से तथा फेज- 5 में मेसर्स जी.ए.विश्वनाथ व मेसर्स के.एल.एस.आर द्वारा

वर्ष 2023 से कार्य प्रारम्भ किया गया है। तीनों कार्यदायी संस्थाओं की फेज वाईज समीक्षा की गयी।

मेसर्स जी.ए.विश्वनाथ- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि फेज-5 के अन्तर्गत 200 परियोजनाये जिसमें 521 राजस्व ग्राम आच्छादित है पर कार्य करने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। इनके द्वारा 368 राजस्व ग्राम में नियमित पेयजल आपूर्ति की जा रही है। जिसमें 111 राजस्व ग्रामों में 100 प्रतिशत तथा 137 ग्रामों में 90 प्रतिशत से 99 प्रतिशत एवं 120 राजस्व ग्रामों में 90 प्रतिशत तक नियमित पेयजल आपूर्ति की जा रही है। रख-रखाव व अनुसूक्षण में 122 योजनाये, (जिसमें 287 राजस्व ग्राम आच्छादित है।) पूर्ण हो चुकी है। ट्रायल एवं रन में केवल 18 योजनाये तथा 55 ग्राम है। संस्था का 199 शिरोपरि जलाशय पूर्ण करने का लक्ष्य है, जिसमें 185 पूर्ण हो चुके हैं। नियमित जलापूर्ति में 90 से 99 प्रतिशत वाले ग्रामों में 100 प्रतिशत तथा 90 प्रतिशत से नीचे वाले ग्रामों को 90 से 99 प्रतिशत श्रेणी में सितम्बर माह तक ले जाने के निर्देश दिये गये। ट्रायल रन में संस्था की प्रगति अच्छी नहीं है। अधिक से अधिक योजनाओं को ट्रायल रन में ले जाने तथा ट्रायल रनसे ओएण्डएम में ले जाने के निर्देश दिये गये। पानी की टंकी का कार्य 199 के सापेक्ष 185 पूर्ण है। अवशेष को शीघ्र पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये। पेयजल आपूर्ति में क्लोरिनेशन के बिना पेयजल की आपूर्ति न किये जाने के निर्देश दिये गये। संस्था के पास 343 मैन पावर है जो कार्य की दृष्टि से बहुत कम है। मैन पावर बढ़ाकर अधिक से अधिक योजनाओं को ट्रायल एवं रन की श्रेणी में ले जाने के निर्देश दिये गये।

मेसर्स के.एल.एस.आर- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि फेज-5 के अन्तर्गत 113 परियोजना जिसमें 319 राजस्व ग्राम आच्छादित है पर कार्य करने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। 319 के सापेक्ष मात्र 48 राजस्व ग्रामों में नियमित पेयजल आपूर्ति की जा रही है। जिसमें मात्र 06 ग्राम में 100 प्रतिशत तथा 20 ग्रामों में 90 प्रतिशत से 99 व 22 ग्रामों में 90 प्रतिशत तक पेयजल आपूर्ति की जा रही है। रख-रखाव एवं अनुसूक्षण (ओएण्डएम) में मात्र 06 योजनाये है, जिसमें 27 राजस्व ग्राम शामिल हैं। ट्रायल रन 14 राजस्व योजनाये है, जिसमें 36 राजस्व ग्राम है। ऐसा प्रतीत हो रहा है ट्रायल रन की श्रेणी से ओएण्डएम श्रेणी में ग्राम नहीं जा रहे हैं। पानी की टंकी 113 के सापेक्ष मात्र 14 तैयार की गयी है। संस्था का कार्य प्रगति अत्यन्त खराब है। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि संस्था के पास स्टाफ एवं मैनपावर नगण्य है, लैब भी नहीं है। जिसके कारण संस्था का कार्य अधिकांश योजनाओं पर एक वर्ष 06 माह से बन्द पड़ा है। संस्था की लापरवाही एवं अकर्मण्यता को देखते हुये अनेकों बार कार्यवाही हेतु अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को पत्र प्रेषित किये जा चुके हैं।

संस्था को तत्काल पर्याप्त मैन पावर व स्टाफ बढ़ाकर कार्य सुधार करने के निर्देश दिये गये। संस्था द्वारा सितम्बर के अन्त तक 05 योजनाये जिसमें 30 राजस्व ग्राम है को 100 प्रतिशत पूर्ण करने का वादा किया गया है। किये गये वादे के अनुसार सितम्बर तक पोंच योजनाओं को पूर्ण करने के निर्देश दिये गये। संस्था को चेतावनी देते हुये सचेत किया गया।

मेसर्स एल.सी.इन्फ्रा- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि संस्था को फेज-2 में 219 परियोजना, जिसमें 488 राजस्व ग्राम आच्छादित है पर कार्य करने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। संस्था के 242 राजस्व ग्रामों में नियमित पेयजल आपूर्ति की जा रही है। 112 राजस्व ग्रामों में 100 प्रतिशत 85 ग्रामों में 90 से 99 प्रतिशत तथा 45 राजस्व ग्रामों में 90 प्रतिशत तक शुद्ध पेयजल आपूर्ति की जा रही है। संस्था की 84 परियोजनाओं के 197 राजस्व ग्राम रख-रखाव व अनुसूक्षण (ओएण्डएम) में है। संस्था ने फेज-2 में वर्ष 2021 से कार्य प्रारम्भ किया है। 219 परियोजना एवं 488 राजस्व ग्रामों के सापेक्ष (ओएण्डएम) रख-रखाव एवं

अनुसूचण में जाने वाले ग्रामों की संख्या सन्तोषजनक नहीं है। ट्रायल एवं रन में 16 योजनाएँ तथा 39 राजस्व ग्राम हैं। ट्रायल रन की प्रगति भी सन्तोषजनक नहीं है। 100 प्रतिशत वाटर सप्लाई वाले ग्रामों को ट्रायल रन की श्रेणी में ले जाकर ओएण्डएम में लाने के निर्देश दिये गये। संस्था को कुल 225 पानी की टंकी बनाने का लक्ष्य था, इसमें 4 टैंक आरओ के हैं। 221 टैंक के सापेक्ष 109 पानी की टंकी बनायी गयी है। फेज-2 में वर्ष 2021 से कार्य प्रारम्भ करने के बावजूद 221 के सापेक्ष मात्र 109 टैंक बनाया गया है। प्रगति अत्यन्त खराब है। अधिशासी अभियन्ता द्वारा बताया गया कि संस्था के पास मात्र 450 मैनपावर है, जबकि कार्य को समय से पूर्ण करने के लिये कम से कम 1200 मैनपावर की आवश्यकता है। रेगुलर वाटर सप्लाई के 99 प्रतिशत से 100 प्रतिशत वाले ग्रामों को सितम्बर के अन्त तक 100 प्रतिशत श्रेणी में ले जाने की आवश्यकता है। 90 प्रतिशत तक आपूर्ति वाले ग्रामों को सितम्बर के अन्त तक 90 से 99 प्रतिशत वाली श्रेणी में शामिल किये जाने के निर्देश दिये गये। अपेक्षित मैनपावर में वृद्धि करके योजना के निर्माण की प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिये गये। ग्राउण्ड लेवल तक रुके हुये टैंक के निर्माण की प्रगति बढ़ाये जाने के निर्देश दिये गये।

Table No-2A: Single Village Scheme Physical Progress.

सिंगल विलेज स्कीम की प्रगति के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन की 159 परियोजनाएँ तथा 18 जल निगम की हैं। सिंगल विलेज स्कीम में जल जीवन मिशन की 42 तथा जल निगम की 18 योजनाएँ कुल 60 योजनाएँ 'हर घर जल' प्रमाणित घोषित हो चुकी हैं। कुल 177 सिंगल विलेज स्कीम्स में से 97 परियोजनाओं में रेगुलर वाटर सप्लाई हो रही है। 97 में से 37 में 100 प्रतिशत, 35 में 90 से 99 प्रतिशत तथा 25 में 90 प्रतिशत तक नियमित वाटर सप्लाई की जा रही है। ओएण्डएम में 87 योजनाएँ भेजी जा चुकी हैं। 15 योजनाएँ ट्रायल रन में हैं। सिंगल विलेज स्कीम्स 159 के सापेक्ष 93 में टैंक बन चुके हैं। स्पष्ट है कि 66 योजनाओं के टैंक अवशेष हैं। मेसर्स एल.सी. इन्फ्रा व मेसर्स के.एल.एस.आर द्वारा सिंगल विलेज स्कीम्स पूर्ण करने में रुचि नहीं ली जा रही है। वित्तीय प्रगति में 41543.68 लाख अनुमानित लागत के सापेक्ष 27726.26 लाख भुगतान हो पाये हैं। अधिशासी अभियन्ता द्वारा बताया गया कि संस्थाओं द्वारा लिखित एवं मौखिक आदेश देने के बावजूद भुगतान के लिये बिल्स प्रस्तुत नहीं किये जा रहे हैं। स्पष्ट है कि संस्थाओं द्वारा सिंगल विलेज स्कीम्स में भी सन्तोषजनक कार्य नहीं किया गया है। 90 से 99 प्रतिशत वाली स्कीम्स को 100 प्रतिशत में तथा 90 प्रतिशत वाली स्कीम को 90 से 99 प्रतिशत श्रेणी में शामिल किये जाने के निर्देश दिये गये तथा ट्रायल रन एवं ओएण्डएम की श्रेणी में प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिये गये। सिंगल विलेज स्कीम्स में टैंक बनाने के लिये मेसर्स एल.सी.इन्फ्रा व मेसर्स के.एल.एस.आर को मैन पावर बढ़ाकर टैंक को पूर्ण करते हुये सिंगल विलेज स्कीम को जनवरी 2027 तक शत-प्रतिशत गुणवत्ता पूर्ण करने के निर्देश दिये गये हैं।

Table No - 3: RWS (Regular Water Supply Villages) disruption.

नियमित पेयजल आपूर्ति वाले ग्रामों में व्यवधान आने के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा तथा कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि कोई व्यवधान नहीं है। अस्थायी रूप से पाईप लीकेज की अस्थायी समस्याएँ आती हैं, तत्काल उनका निराकरण कर दिया जाता है। सभी सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं को क्लोरीनयुक्त शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति किये जाने हेतु निर्देश दिये गये।

Table No-4: Certification/Jal Arpan/Jal Aikya/RPWS/Road Restoration.

अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन में कुल 1452 राजस्व ग्राम कार्यदायी संस्थाओं को आवंटित किये गये हैं। मेसर्स जी.ए. इन्फ्रा को 521, मेसर्स के.एल.एस.आर को 319, मेसर्स एल.सी. 488 को , मेसर्स सुधाकर इन्फ्राटेक (जल निगम) को 124 राजस्व ग्राम आवंटित हैं। कुल 1452 में से मात्र 378 राजस्व ग्राम सर्टीफाइड

ग्राम घोषित है। 153 ग्राम पंचायत के 313 राजस्व ग्रामों में जल अर्पण का कार्य किया गया है। 305 राजस्व ग्रामों में जल आंकलन का कार्य हो पाया है। 852 राजस्व ग्रामों में 100 प्रतिशत रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण किया गया है। सर्टीफाइड ग्रामों व जल अर्पण वाले ग्रामों की प्रगति सन्तोषजनक नहीं है। सर्टीफाइड ग्राम/जल अर्पण व जल आंकलन में मेसर्स के.एल.एस.आर की प्रगति सर्वाधिक खराब है। मेसर्स के.एल.एस.आर को कड़ी चेतावनी के साथ प्रगति लाने के लिये सचेत किया गया। रोड रेस्टोरेशन में 852 ग्रामों में 100 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर दिया गया है, परन्तु अन्तिम रूप से रोड रेस्टोरेशन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वर्षात के मौसम के कारण रास्तों/मार्गों के क्षतिग्रस्त होने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। माओ मुख्यमंत्री जी के स्तर से भी रोड रेस्टोरेशन के लिये कड़े निर्देश जारी किये गये हैं। सर्टीफाइड ग्राम/जल अर्पण तथा रोड रेस्टोरेशन में प्रगति लाने हेतु कड़े निर्देश दिये गये।

Table No - 4A : RPWS Village Details.

अधिकांसी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि मऊ में कुल 1470 राजस्व ग्रामों की (आरपीडब्ल्यूएसएस) रूरलपाइप वाटर सप्लाई स्कीम की आईडी किएट किये जाने का लक्ष्य निर्धारित था। 1463 की आईडी किएट की जा चुकी है। कुथीजाफरपुर, बेलचौरा, चमरियावां, बडागोंव, परसपुरा 05 ग्राम नगरीय निकाय में हैं। दरगाह व चकगोकुल 02 ग्रामों की एलजीडी कोड की मैपिंग नहीं हुयी है। इस प्रकार जनपद मऊ की प्रगति शत-प्रतिशत पूर्ण है। नगरीय निकाय वाले ग्रामों को पोर्टल से डिलीट कराने एवं एलजीडी मैपिंग का निराकरण कराने के निर्देश दिये गये।

Table No-5: Components Wise Physical Progress.

अधिकांसी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन के विभिन्न घटकों की भौतिक प्रगति द्यूबवेल में 98.81 प्रतिशत, पम्प हाउस में 96.70 प्रतिशत, क्लोरीनीकरण प्रगति 94.96 प्रतिशत, ओवर हेड टैंक 57.36 प्रतिशत, पाइप लाइन बिछाने का कार्य 94.79 प्रतिशत, सौर उर्जा प्लांट 75.63 प्रतिशत, घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) 94.59 प्रतिशत, सड़क मरम्मत का कार्य 99.26 प्रतिशत, 100 प्रतिशत सड़क मरम्मत का कार्य 64.16 प्रतिशत, कमीशनिंग गोंव 52.03 प्रतिशत, नियमित जल आपूर्ति 49.55 प्रतिशत की प्रगति हुई है। क्लोरीनीकरण, ओवर हेड टैंक 100 प्रतिशत, रोड रेस्टोरेशन, कमीशनिंग तथा नियमित जल आपूर्ति की प्रगति सन्तोषजनक नहीं है। कार्यदायी संस्थाओं/टीपीआई को प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिये गये तथा अधिकांसी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) को नियमित अनुश्रवण करने के लिये निर्देशित किया गया।

Table No-6: Unified Command and Control System (UCCS)-Automation.

यूनिफाइड एण्ड कंट्रोल सिस्टम तथा ऑटोमेशन- जल निगम की योजनाओं को शामिल करते हुये कुल 585 योजनाओं में इन्टीग्रेटेड में 186 लाइव में 154 ओएण्डएम 212 में इन्टीग्रेटेड 163 लाइव 141 की प्रगति है। लाइव देखने पर प्रदर्शित होने की प्रक्रिया धीमी पायी गयी। अधिकांसी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि 2जी सिमकार्ड के कारण प्रदर्शन प्रभावित हो रहा है, जिसे ठीक किये जाने के निर्देश दिये गये।

Table No - 7: Grievance Redressal System.

Grievance Redressal पोर्टल में कुल 971 शिकायतें हैं, जिसमें 966 क्लोज हो चुकी हैं। 05 अवशेष हैं। अवशेष 05 प्रकरण मेसर्स के.एल.एस.आर के हैं। मेसर्स के.एल.एस.आर द्वारा शिकायतों के निस्तारण में घोर लापरवाही की गयी है। कड़ी चेतावनी के साथ एक सप्ताह में गुणवत्ता से कार्य पूर्ण कर निस्तारण के लिये निर्देश दिये गये।

Table No.8 : Arsenic/Fluoride/JE/AES से प्रभावित क्षेत्रों का विवरण -

अधिकांसी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि जेई/एईएस में एक ग्राम पड़री प्रभावित था। सभी घरों में कनेक्शन पूर्ण कर डाइरेक्ट क्लोरीनयुक्त शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल की

आपूर्ति की जा रही है। फलोराइड में चार ग्राम प्रभावित है। बेलौझा, अतरारी, सरखों (परदहों), प्यारेपुर सलामुद्दीनपुर है। अधिशासी अभियन्ता द्वारा बताया गया कि जल निगम की पुरानी योजना प्यारेपुर सलामुद्दीनपुर तथा सरखों (परदहों) है, जहाँ पर कार्य प्रगति पर है। शीघ्र पूर्ण कर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जायेगी। बेलौझा में मेसर्स एल.सी. इन्फ्रा तथा अतरारी में मेसर्स के.एल.एस.आर की परियोजना है। दोनों संस्थाओं को शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्वक कार्य पूर्ण कर पाईप लाइन से क्लोरीनयुक्त शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करने के निर्देश दिये गये।

Table No-9: Water Quality.

पेयजल गुणवत्ता : अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि पेयजल गुणवत्ता के लिये जल निगम परिसर में स्थित जनपद स्तरीय प्रयोगशाला में सैम्पल मंगाकर नियमित जाँच की जा रही है। प्रत्येक राजस्व ग्राम में पंजीकृत एफटीके महिलाओं के माध्यम से गुणवत्ता की जाँच कर ऑनलाइन अपलोड किया जा रहा है। स्कूल एवं आँगनवाड़ी केन्द्रों के जल स्रोतों की भी जाँच की जा रही है। जल गुणवत्ता परीक्षण की कार्यवाही निरन्तर जारी रखने के निर्देश दिये गये।

Table No - 10: Automation Integrated Schemes.

अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि सभी पेयजल परियोजनाओं पर क्लोरीनेशन प्लान्ट लगाने का प्राविधान है। पूर्ण होने वाली परियोजना तथा नियमित पेयजल आपूर्ति होने वाले ग्रामों में क्लोरीनेशन प्लान्ट लगाकर शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। लाइव मॉनिटरिंग के लिये भी सिस्टम लगाये गये हैं। कहीं से भी लाइव देखा जा सकता है। पेयजल परियोजनाओं के निर्माण की गुणवत्ता का मानक सुनिश्चित करने हेतु थर्डपार्टी के लिये मेघज टेक्नो कान्सेप्ट लि० की टीम टीपीआई के रूप में नियुक्त की गयी है। टीपीआई प्रतिनिधि के पूछने पर बताया गया कि कुल 11 स्टाफ है। गुणवत्ता के सम्बन्ध में बताया गया कि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व आरएफआई अपलोड नहीं की जाती है, जिससे गुणवत्ता की निगरानी में परेशानी होती है। कार्यदायी संस्थाओं को कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व आरएफआई अपलोड करने के निर्देश दिये गये।

अगले माह की समीक्षा बैठक के लिये विगत माह व वर्तमान तक की प्रगति का तुलनात्मक विवरण पत्र प्रस्तुत करने के लिये अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया।

बैठक सघन्यवाद सम्पन्न हुई।

Digitally signed by
RAMESHWAR DAYAL
Date: 18-09-2026
13:25:40

अधिशासी अभियन्ता
जल निगम (ग्रामीण)
मरु

Digitally signed by
VIVEK KUMAR SRIVASTAV
Date: 18-09-2026
20:01:09

मुख्य विकास अधिकारी
मरु

Digitally signed by
Anand Vardhan
Date: 19-09-2026
10:34:39

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
(बीडब्ल्यूएसएम)
मरु